मेक इन यूपी की शुरुआत, पहली बार 50000 उद्योगों के लिए ई मार्केट

उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण की पहल, आपस में ही खरीद-फरोख्त से जीएसटी और रोजगार बढ़ेंगे

अभिषेक गुप्ता

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण 155 औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित करीब 50 हजार इकाइयों के लिए एक कामन ई मार्केट प्लेटफॉर्म तैयार कर रहा है।

इसका उद्देश्य प्रदेश की इकाइयों से ही कच्चा माल खरीदने, फिनिश्ड उत्पाद तैयार करने और मार्केट में भेजने वाली इकाइयों के बीच सेतु का काम करना है। इससे दूसरे राज्यों से माल की खरीद के बजाय यूपी के उद्यमी आपस में ही माल की खरीद फरोख्त करेंगे। इस पहल से लॉजिस्टिक और वेयरहाउसिंग में खर्च होने वाले करीब 20000 करोड़ रुपये यूपी के उद्यमियों के बचेंगे। वहीं राजस्व में जीएसटी सहित अन्य टैक्स के रूप में भी 7 से 10 फीसदी तक का इजाफा होगा। देश में औद्योगिक इकाइयों के लिए यह शुरुआत पहली बार की जा रही है, जिसे नए साल में लॉन्च कर दिया जाएगा।

औद्योगिक इकाइयों का 12 फीसदी से ज्यादा बढ़ेगा कारोबार

प्रदेश में 17 सेक्टर में 50 हजार इकाइयां हैं। कच्चा माल आधारित और फिनिश्ड गुड प्रोडक्ट क्लस्टर हैं। कच्चा माल वाला क्लस्टर पूर्व से पश्चिम की तरफ आता है। वहीं फिनिश्ड उत्पाद वाला क्लस्टर पश्चिम से पूर्व की तरफ उत्पाद भेजता है। यूपीसीडा ने 'मेक इन यूपी' की अवधारणा के साथ ये इनोवेशन किया है। इसके तहत अगर लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद, झांसी या किसी भी जिले में स्थित इकाई दूसरे राज्य से कच्चा माल मंगा रही है, जबकि इकाई को वहीं से किसी अन्य इकाई द्वारा तैयार किया जा रहा कच्चा मिल सकता है। इसकी जानकारी होते ही दोनों इकाइयां बाहर के बजाय आपस में सौदे करेंगी। इससे यूपी की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। राज्य का टैक्स राज्य में रहेगा। लाजिस्टिक कीमत कम होगी। वेयरहाउसिंग का खर्च बचेगा। सप्लायर, ग्राहक, खरीदार और तैयार उत्पादों की लागत पर सीधा असर आएगा। यूपी का सकल घरेलू उत्पाद करीब 2.75 लाख करोड़ है। कम से कम 7 फीसदी लाजिस्टिक और निर्माण में लागत घटेगी। उद्यमियों की केवल इन दो क्षेत्रों में ही 20 हजार करोड़ की बचत होगी।

उद्यमियों के आपस में सौदों के लिए कोई ई-मार्केट प्लेस नहीं है। प्राधिकरण अगले वर्ष यूपीसीडा ई मार्केट प्लेस लांच करेगा। इस प्लेटफार्म के जरिये यूपीसीडा के 155 औद्योगिक क्षेत्रों की 50 हजार से ज्यादा इकाइयों को कॉमन प्लेटफार्म दिया जाएगा। दरअसल बड़ी संख्या में कच्चा माल, पैकेजिंग, फिनिशिंग, मार्केटिंग और विपणन से जुड़ी इकाइयां यूपी में इन्ही क्षेत्रों में हैं लेकिन उद्यमियों को इसकी जानकारी न होने के कारण अन्य राज्यों से माल मंगाते हैं। इस प्लेटफार्म से यूपी की इकाइयों का कारोबार बढ़ेगा। इसका असर रोजगार और जीएसटी पर आएगा, जो दस खरब डालर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य में अहम भूमिका निभाएगा।

-मयूर महेश्वरी, सीईओ, यूपीसीडा